BIS का प्रोजेक्ट नेक्सस

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में [भारतीय रिज़र्व बैंक](#) (Reserve Bank of India- RBI) **प्रोजेक्ट नेक्सस (Project Nexus)** में शामिल हो गया है, जो **घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों (Fast Payments Systems- FPS) को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा** पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिये एक **बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल** है।

प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है?

- **परिचय:**
  - **प्रोजेक्ट नेक्सस** की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (Bank for International Settlements- BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है।
  - इसका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक घरेलू **त्वरित भुगतान प्रणालियों** (Instant Payment Systems- IPS) को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ाना है।
  - यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाली **पहली BIS इनोवेशन हब परियोजना** है।
- **सदस्य:**
  - प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य **दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN)** के चार देशों अर्थात् **मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत** के FPS को जोड़ना है, जो इस प्लेटफॉर्म के संस्थापक सदस्य तथा प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।
    - भविष्य में **इंडोनेशिया** भी इस मंच से जुड़ जाएगा।
  - इस संबंध में एक समझौते पर **स्विट्ज़रलैंड के बासेल में BIS और संस्थापक देशों** के केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किये गए।
- **लाभ:**
  - प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य IPS को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के तरीके को सुव्यवस्थित करना है, तथा एकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्शनों को केंद्रीकृत करके प्रत्येक **नए देश के साथ कस्टम कनेक्शन की आवश्यकता** को समाप्त करना है।
  - यह **एकल कनेक्शन तीव्र भुगतान प्रणाली को नेटवर्क पर अन्य सभी देशों तक पहुँचने** की अनुमति देता है।
    - BIS के अनुसार, IPS को जोड़ने से प्रेषक से प्राप्तकर्त्ता तक **60 सेकंड के भीतर (अधिकांश मामलों में)** सीमा पार भुगतान संभव हो सकता है।
  - जबकि भारत तथा उसके साझेदार **देश FPS की द्विपक्षीय संचार माध्यम से लाभान्वित** होते रहेंगे, बहुपक्षीय दृष्टिकोण भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच का विस्तार करने में RBI के प्रयासों को और अधिक गति प्रदान करेगा।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) [UPI](#) को क्रॉस-बॉर्डर **पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) भुगतानों के लिये उनके संबंधित FPS से जोड़ने हेतु विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग** प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिये भूटान, [UAE](#), [फ्राँस](#), [श्रीलंका](#), मॉरीशस।

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

- **वर्ष 1930 में स्थापित [BIS](#) का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका विश्व [सकल घरेलू उत्पाद](#) में लगभग 95% योगदान है।**
- इसका मुख्य कार्यालय **बेसल, स्विट्जरलैंड** में है और इसके दो प्रतिनिधि कार्यालय (हांगकांग SAR तथा मैक्सिको सिटी) हैं, साथ ही दुनिया भर में इनोवेशन हब सेंटर भी हैं।
- **इनोवेशन BIS 2025,** इसकी **मध्यम अवधि की रणनीति** है जो तेज़ी से बदलती दुनिया में केंद्रीय बैंकिंग समुदाय की सेवा करने के लिये प्रौद्योगिकी और नए सहयोग माध्यमों का लाभ उठाती है।
- बेसल बैंकिंग समझौते, [**बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS)**](#) द्वारा निर्धारित वैश्विक नियम हैं, जो स्विट्जरलैंड के बेसल में **अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)** के अंतर्गत कार्य करते हैं, और बैंकिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- यह केंद्रीय बैंकों को उपलब्ध कराता है**:**
  - संवाद एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक मंच
  - उत्तरदायित्वपूर्ण नवाचार एवं ज्ञान-साझाकरण के लिये एक मंच

- मुख्य नीतिगत मुद्दों पर गहन वश्लिेषण और अंतर्दृष्टि
- मज़बूत एवं प्रतस्पिर्द्धी वत्तिीय सेवाएँ

//

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अर्थ है डिजिटल डिवाइस या चैनल (बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी, क्यूआर कोड आदि) का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे भुगतान खाते में धन स्थानांतरित करना।

NPCI द्वारा भुगतान प्रणाली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान हेतु एक व्यापक इकाई है (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)।

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

- खुदरा ग्राहकों के लिये
- **सीमा-** ₹1-5 लाख (शुल्क+जीएसटी)
- 24/7(तत्काल निपटान)
- **प्रदाता:** बैंक, पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- IMPS आधारित डिजिटल भुगतान ऐप के लिये प्रौद्योगिकी
- पुश एवं पुल हस्तांतरण
- फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया
- **UPI-Lite+NFC:** ऑफलाइन भुगतान के लिये
- **BHIM-UPI:** धन हस्तांतरण ऐप

रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे (RuPay)

- **3 चैनलों में काम करता है: -** एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल
- PMJDY के साथ निशुल्क दिया जाता है
- विदेशों में भी अपनाया गया (जैसे मॉरीशस)

विभिन्न पहलें

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS)
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
- PAI चैटबॉट (एआई आधारित क्वेरी रिज़ॉल्यूशन)
- भारत QR
- ई-रूपी (e-RUPI)
- आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)

RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)

- उच्च मूल्य के हस्तांतरण हेतु
- **निम्न सीमा:** ₹2 लाख (कोई ऊपरी सीमा नहीं) (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (तत्काल निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (LPSS)

- NEFT/RTGS के लिये RBI का आपातकालीन विकल्प
- अस्थायी, पोर्टेबल समाधान

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)

- मध्यम-श्रेणी के हस्तांतरण हेतु
- RBI द्वारा कोई सीमा नहीं (कोई शुल्क नहीं)
- 24/7 (30 मिनट के अंतराल पर बैंकों के बीच सकल राशि का निपटान)
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

डिजिटल भुगतान नियामक निकाय/सूचकांक

- डिजिटल हस्तांतरण लोकपाल
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)

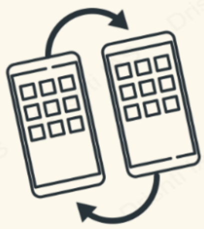

Drishti IAS

और पढ़ें: [एफिल टावर से हुआ UPI का लॉन्च](), [श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाएँ]()

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????

प्रश्न. डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. BHIM एप उपयोग करने वालों के लिये यह एप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन अंतरण करना संभव बनाता है।
2. जहाँ एक चिप-पिन डेबिट कार्ड में प्रामाणीकरण के चार घटक होते हैं, BHIM एप में प्रामाणीकरण के सिर्फ दो घटक होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. 'एकीकृत भुगतान अंतराप्रष्ठ (यूनफिाइड पेमेंट्स इंटरफेस/UPI)' को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? (2017)

(a) ऑनलाइन भुगतानों के लिये मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे।
(b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।
(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।
(d) निर्धन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज़) का प्रत्यक्ष अंतरण (डाइरेक्ट ट्रांसफर) बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है।
2. NPCI ने रुपे कार्ड भुगतान योजना शुरू की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/project-nexus-of-bis